श्री मंगुभाई पटेल

राज्यपाल, मध्यप्रदेश

का

अभिभाषण

मध्यप्रदेश विधानसभा अधिवेशन

8, फाल्गुन शुक्ल, 1944 शक भोपाल, सोमवार 27 फरवरी, 2023

माननीय अध्यक्ष एवं माननीय सदस्यगण,

1. सभी सम्मानीय सदस्यों का हार्दिक स्वागत।

2. पन्द्रहवीं विधानसभा के पाँचवें और अंतिम बजट सत्र में सदन को सम्बोधित करते हुए मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है। यह निश्चय ही गर्व एवं सौभाग्य का विषय है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में अमृत-महोत्सव से लेकर अमृत-काल तक समृद्ध, विकसित एवं आत्म-निर्भर भारत के निर्माण की एक नई महायात्रा प्रारम्भ हो गई है। मध्यप्रदेश भी कदम से कदम और कंधे से कंधा मिलाकर माननीय प्रधानमंत्री जी के सपनों एवं संकल्पों की सिद्धि में अपना हर सम्भव योगदान दे रहा है।मेरी सरकार आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण की प्रतिबद्धता का प्रमाण भी है और प्रतिबिम्ब भी ।

3. आज़ादी के अमृत-काल में माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व में जी-20 समूह की अध्यक्षता वैश्विक परिदृश्य में भारत के स्वर्ण- युग की शंख-ध्वनि है।

"एक धरती - एक परिवार - एक भविष्य" की थीम जी-20 को 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के भारतीय दर्शन की आभा से आलोकित कर रही है। मध्यप्रदेश को जी-20 समूह की 8 बैठकों की मेज़बानी का सुअवसर प्राप्त हुआ है। अब तक 3 बैठकें क्रमश: भोपाल, इंदौर और खजुराहो में आयोजित हो चुकी हैं, जिनके माध्यम से मध्यप्रदेश की छवि पूरी दुनिया में उज्ज्वल हुई है।

4. मध्यप्रदेश की धरती पर आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के दौरान 70 से अधिक देशों से आए 3 हजार 500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इंदौर में निर्मित 'नमो ग्लोबल गार्डन' प्रवासी भारतीयों द्वारा लगाए गए पौधों के रूप में आयोजन की सुखद स्मृतियों को चिरकाल तक जीवंत बनाए रखेगा।

5. मेरी सरकार का सर्वोपरि लक्ष्य है- मध्यप्रदेश की जनता की जिन्दगी को बदलना । प्रदेश के गाँव - गाँव और शहर - शहर में निकाली गई विकास यात्राएँ सच्चे अर्थों में जनसेवा का महायज्ञ बन गई हैं। सरकार की योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी देते विकास-रथ के साथ विकास-पताका हाथ में लिए जनता उत्साह और उमंग के साथ इन यात्राओं में शामिल हुई।

दिनांक 05 फरवरी से प्रारम्भ विकास यात्राओं के दौरान बड़ी संख्या में विकास कार्यों का लोकार्पण एवं भूमि-पूजन किया गया है। विकास यात्रा ने जनता की यात्रा के रूप में सफलता और रचनात्मकता के नए आयाम स्थापित किये हैं।

6. मेरी सरकार अधोसंरचना विकास की परियोजनाओं को मिशन मोड में क्रियान्वित कर रही है। विगत 2 वित्तीय वर्षों में लगभग 12 हजार करोड़ रुपए का व्यय कर 8 हजार किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों का निर्माण, उन्नयन एवं नवीनीकरण तथा 69 पुलों का निर्माण किया गया है। प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग अंतर्गत 27 हजार करोड़ रुपए से अधिक के सड़क निर्माण कार्य प्रगति पर है। विगत 3 वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना अंतर्गत 17 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक के मार्गों की स्वीकृति प्रदान की गई है। रीवा-सीधी 6 लेन एक्वाडक्ट टनल के निर्माण ने आर्थिक, सामाजिक और औद्योगिक विकास को एक नई दिशा दी है। भारत सरकार के सहयोग से निर्मित हो रहे अटल प्रगति पथ सहित 5 एक्सप्रेस हाइवे मध्यप्रदेश की तस्वीर को बदलकर रख देंगे।

नर्मदा एक्सप्रेस-वे और विंध्य एक्सप्रेस-वे, समृद्धि और विकास के महामार्ग साबित होंगे। सिंगरौली में नवीन हवाई पट्टी, रीवा में एयरपोर्ट निर्माण तथा ग्वालियर में विमानतल के विस्तार और विकास से आम आदमी के हवाई यात्रा के सपने साकार होंगे।

7. मेरी सरकार गाँव-गाँव में और खेत-खेत तक सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करा रही है। अब तक 45 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी हैं। जल संसाधन विभाग द्वारा निर्माणाधीन 475 सिंचाई परियोजनाओं के माध्यम से 28 लाख हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता विकसित की जा रही है। नर्मदा कछार की 24 हजार 500 करोड़ रुपए से अधिक लागत की 5 लाख 50 हजार हेक्टेयर से अधिक की सिंचाई क्षमता वाली 12 परियोजनाओं के निर्माण की कार्यवाहियाँ प्रारंभ हो गई हैं। रुपए 44 हजार 600 करोड़ से अधिक लागत की केन-बेतवा लिंक परियोजना के प्रथम चरण में बांध, लिंक नहर तथा पॉवर हाउस का निर्माण कार्य इस वर्ष प्रारंभ करने का लक्ष्य है।

8. प्रदेश में ऊर्जा अधोसंरचना, आत्म-निर्भरता की परिचायक है और अंत्योदय की भी। हमारी समेकित ऊर्जा क्षमता 28 हजार मेगावाट से भी अधिक हो गई है।

मेरी सरकार द्वारा अटल गृह ज्योति योजना, अटल कृषि ज्योति योजना, अनुसूचित जाति-जनजाति के पात्र कृषकों को नि:शुल्क विद्युत प्रदाय योजना तथा कुसुम योजना के माध्यम से घरेलू एवं कृषि उपभोक्ताओं को निरंतर लाभान्वित किया जा रहा है। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए नवकरणीय ऊर्जा नीति-2022 लागू की गई है। प्रदेश में 2 हजार 850 मेगावाट की सोलर पार्क, फ्लोटिंग सोलर पार्क तथा पवन एवं सोलर हाईब्रिड परियोजनाओं का विकास किया जा रहा है। ऊर्जा साक्षरता अभियान से 12 लाख से अधिक नागरिकों को जोड़ा गया है।

9. अधोसंरचना निवेश के साथ औद्योगिक निवेश के संगम से चहुँमुखी विकास मेरी सरकार का मंत्र है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट-2023 मध्यप्रदेश के लिए अभूतपूर्व रही है। देश-विदेश से प्रदेश में 15 लाख 42 हजार करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना राज्य सरकार की उद्योग हितैषी नीतियों एवं शासन तंत्र पर निवेशकों के अटूट भरोसे का ही परिणाम है। इन निवेश प्रस्तावों से लगभग 29 लाख रोज़गार के नए अवसर सृजित होंगे। प्रदेश में 12 नए औद्योगिक क्षेत्र और 2 आई.टी. पार्क के विकास और 16 विद्यमान औद्योगिक क्षेत्रों के उन्नयन का कार्य लगभग 2 हजार 400 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है ।

रतलाम, पीथमपुर एवं देवास में नए निवेश क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं। विक्रम उद्योगपुरी जिला उज्जैन में मेडिकल डिवाइसेस पार्क में मेडिकल डिवाइस उत्पादन इकाइयों की स्थापना प्रारंभ हो गई है। प्रदेश में 1 हजार 400 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर इन्दौर-पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर तथा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क विकसित किए जाने की योजना है।

10. प्रदेश में 22 MSME क्लस्टर स्वीकृत किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से लगभग 5 हजार 400 करोड़ रुपए का निवेश और 50 हजार प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोज़गार का सृजन संभावित है। मध्यप्रदेश को देश का स्टार्ट-अप हब बनाने के लक्ष्य के साथ स्टार्ट-अप नीति-2022 लागू करते हुए ऑनलाईन पोर्टल एवं स्टार्ट-अप सेन्टर की स्थापना की गई है। इन्दौर के सुपर कॉरिडोर में 22 एकड़ ज़मीन पर 35 मंजिला स्टार्ट-अप पार्क निर्मित किया जाएगा, जिससे 20 हजार रोज़गार के अवसर सृजित होंगे। मध्यप्रदेश के हथकरघा वस्त्रों के फैशन शो इन्दौर और मुम्बई फैशन वीक से लेकर न्यूयार्क फैशन वीक तक अपनी छाप छोड़कर आए हैं। प्रदेश के रेशम उत्पादक किसानों को ककून का उचित मूल्य दिलाने के लिए नर्मदापुरम जिले में ककून मण्डी प्रारंभ की गई है, जिससे किसानों की आमदनी में लगभग दोगुनी वृद्धि हुई है।

11. माननीय प्रधानमंत्री जी के "सस्टेनेबल एग्रीकल्चर" के मंत्र को मेरी सरकार ने अपना मिशन बनाया है। कृषि का विविधीकरण, जैविक खेती, प्राकृतिक खेती, नवीनतम तकनीकों का उपयोग, स्वाईल हेल्थ पर विशेष ध्यान, नरवई जलाने की प्रथा का हतोत्साहन एवं किसानों को आधुनिक कृषि का प्रशिक्षण आदि विभिन्न प्रयासों के माध्यम से खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने और किसानों की आय बढ़ाने में सरकार कोई कोर-कसर नहीं छोड़ रही है। विभिन्न किसान-हितैषी योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से 2 लाख 25 हजार करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसानों के खातों में अंतरित की गई है। मेरी सरकार अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष-2023 में मिलेट मिशन को तेजी से आगे बढ़ा रही है।

12. मेरी सरकार प्रदेश में सहकारिता आंदोलन को मज़बूत करने के लिए सुनियोजित रणनीति के साथ काम कर रही है। विगत 2 वित्तीय वर्षों में किसानों को 32 हजार 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि के अल्पावधि ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर उपलब्ध कराए गए हैं। गैर परंपरागत क्षेत्रों जैसे - पर्यटन,

ग्रामीण परिवहन, सेवा प्रदाय, आई.टी., सामाजिक वानिकी, उद्यानिकी, श्रम, भण्डारण, जैविक कृषि, गणवेश, सुरक्षा, महिला गृह उद्योग, कला, स्वास्थ्य, कौशल उन्नयन, मुर्गी पालन, तकनीकी शिक्षा आदि में भी 800 से अधिक नवीन सहकारी संस्थाओं का संचालन प्रारंभ किया गया है। सहकारी क्षेत्रों में 43 किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत किए गए हैं।

13. मेरी सरकार कृषि से जुड़े सभी क्षेत्रों में किसानों की समृद्धि के लक्ष्य के साथ कार्य कर रही है। प्रदेश में 3 लाख 64 हजार पशुपालकों को किसान क्रेडिट कार्ड स्वीकृत किए गए हैं, जो देश में सर्वाधिक हैं। मुख्यमंत्री डेयरी प्लस योजना के अंतर्गत अब तक 447 डेयरियाँ स्थापित की जा चुकी हैं। पशुपालकों को घर पहुँच पशु चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 400 से अधिक चलित पशु चिकित्सा इकाइयों के संचालन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री दुधारू पशु प्रदाय योजना के अंतर्गत बैगा, सहरिया एवं भारिया जनजातियों के हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा। पिछले पाँच वर्षों में प्रदेश में मछली उत्पादन बढ़कर दोगुना हो गया है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन के लिए मध्यप्रदेश को देश में विशेष श्रेणी का उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है।